



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2008/भाद्र 7, 1930

No. 473]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2008/BHADRA 7, 1930

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 625(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित तबत धारा की उप-धारा (1) और धारा 30(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2004 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. नियम 8 का संशोधन :—रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उप-नियम (1) के अधीन पेंशन सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए चार हजार सात सौ सोलह रु. प्रति वर्ष की दर से संगणित की जाएगी किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगी कि इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की कुल रकम, ऐसी किसी पेंशन की रकम सहित जिसके अंतर्गत ऐसी पेंशन, यदि कोई हो, का संगणित भाग भी है, जो अधिकरण में पद धारण

करते हुए प्राप्त किया गया है या जिसे प्राप्त करने का वह हकदार है, दो लाख चौतीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी।”

[सं. 94/टी सी (आर सी टी)/2-2 पार्ट]

सुनील कुमार, कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत

स्पष्टीकरण ज्ञापन

1. अप्रैल, 2004 से लामू पेंशन की संगणना के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में मंहगाई भत्ते का 50% जोड़े जाने को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल, 2004 से अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय पेंशन की ऊपरी सीमा को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया गया है। अतः रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 के उप-नियम (2) को 1 अप्रैल, 2004 से अर्थात् भूतलम्बी प्रभाव से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त संशोधन को भूतलम्बी प्रभाव दिए जाने से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी : रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 844(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं.(1) सा.का.नि. 726(अ) तारीख 6 दिसम्बर, 1991, (2) सा.का.नि. 185(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1996, (3) सा.का.नि. 733(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2000 और (4) सा.का.नि. 386(अ), तारीख 25 मई, 2001 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2008

G.S.R. 625(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (b) of sub-section (2), of Section 30 and Section 30A, of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st April, 2004.

2. Amendment of rule 8.—In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum for each completed year of service subject to the condition that the aggregate amount of pension payable under this rule, together with the amount of any pension including commuted portion

of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed rupees two lakh thirty four thousand per annum”.

(No. 94/TC (RCT)/2-2 PL)

SUNIL KUMAR, Executive Director, Public Grievances

EXPLANATORY MEMORANDUM

In view of merger of 50% of Dearness Allowances with basic pay of the Central Government employees for the purpose of calculation of pension with effect from the 1st April, 2004, it has been decided to revise the upper limit of pension payable to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Tribunal with effect from the 1st April, 2004. It is, therefore, proposed to amend sub-rule (2) of rule 8 of the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 with effect from the 1st April, 2004 i.e. with retrospective effect.

2. It is certified that no person shall be adversely affected by the aforesaid amendment being given retrospective effect.

Footnote: The Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, published in the Gazette of India, vide, notification No. G.S.R. 844(E), dated 19th September, 1989 and subsequently amended by (1) G.S.R. 726(E), dated 6th December, 1991, (2) G.S.R. 185(E), dated 11th April, 1996, (3) G.S.R. 733(E), dated 21st September, 2000 and (4) G.S.R. 386(E), dated 25th May, 2001.